भारतीय उद्योगपति और ब्रिटेन के कुछ व्यापारियों तथा मिल मालिकों के बीच जो चर्चा हुई थी, क्या सरकार ने उसका अध्ययन कर लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका परिणाम क्या है ?

†[STEEL PLANT IN INDIA BY INDIAN AND BRITISH INDUSTRIALISTS

*349. SHRI KRISHNAKANT VYAS: Will the Minister for COMMERCE AND INDUSTRY be pleased to state:

(a) whether Government have studied the negotiations held recently in connection with the establishment of a steel plant in India between an Indian Industrialist and certain merchants and mill owners of Britain; and

(b) if so, with what results?]

उद्योग मंत्री (श्री नित्यानन्द कानूनगो): सरकार की जानकारी में १९५५ में ऐसी कोई चर्चा नही हुई । इस प्रकार की कुछ चर्चायें १९५४ में अवश्य हुई थीं किन्तु उनका कोई परिणाम नहीं निकला क्योंकि सरकार ने उन प्रस्तावों का समर्थन नही किया था ।

†[THE MINISTER FOR INDUSTRIES (SHRI N. KANUNGO): There were no such negotiations in 1955 within the knowledge of Government. There were some talks of this nature in 1954 which, however, produced no results as Government did not favour the proposals.]

SHRI M. VALIULLA: May I know whether any plant is likely to be installed there with the help of Britain?

SHRI N. KANUNGO: Certain British steel people were invited to give us an offer and they have submitted their preliminary report. Their estimates are likely to be in our hands by January and after that, a decision will be taken.

दक्षिण अफ्रीका में जातिभेद की जांच के लिये नियुक्त संयुक्त राष्ट्र संघ आयोग द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन

***३५०. श्री कृष्णकान्त व्यास :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दक्षिण अफ्रीका में जातिभेद की जांच के लिये जो आयोग संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा नियुक्त किया गया था उसने क्या संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा को अपना प्रतिवेदन दे दिया है ;

(ख) यदि हां, तो प्रतिवेदन की मुख्य बातें क्या है ; और

(ग) क्या महासभा ने इस प्रतिवेदन पर विचार कर लिया है ; यदि हां तो उसका क्या परिणाम निकला?

†[REPORT SUBMITTED BY THE U.N. COMMISSION ON RACIAL DISCRIMINATION IN SOUTH AFRICA

*350. SHRI KRISHNAKANT VYAS: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether the Commission appointed by the United Nations Organization for making an enquiry into racial discrimination in South Africa, has submitted its report to the United Nations General Assembly;

(b) if so, what are the main points of the report; and

(c) whether the General Assembly has considered this report and if so, with what results?]

वैदेशिक कार्य उपमंत्री (श्री अनिल के० चन्दा) : (क) जी हां ।

(ख) रिपोर्ट में कमीशन ने :

(१) दक्षिण अफ्रीका में नये विधान और कानूनों के अर्थों का अध्ययन और पड़ताल करना जारी रखा है, और

†English translation.

(२) अगस्त, १९५४ और जुलाई, १९५५ के बीच हुई कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं का वर्णनात्मक ब्यौरा, जिसमें दक्षिण अफ्रीका की जातीय-स्थिति पर असर या रोशनी पड़ी, पेश किया है ।

(ग) संयुक्त राष्ट्र जनरल असेम्बली की तदर्थ राजनैतिक समिति ने रिपोर्ट पर विचार किया और ९ नवम्बर, १९५५ को एक प्रस्ताव पास कर दिया । दूसरी बातों के साथ साथ, प्रस्ताव मे कमीशन से प्रार्थना की गई कि वह दक्षिण अफ्रीका की जातीय स्थिति को बराबर देखता रहे और जनरल असेम्बली के अगले अधिवेशन में रिपोर्ट दे । ६ दिसम्बर, १९५५ को जनरल असेम्बली के सम्पूर्ण अधिवेशन में यह प्रस्ताव विचार के लिये पेश हुआ । प्रस्ताव के उस पैराग्राफ को, जिसमें कमीशन को एक और साल के लिये फिर नियुक्त करने का सुझाव दिया गया था, लागू होने के लिये आवश्यक दो-तिहाई बहुमत में से एक मत कम मिला । बाक़ी पैराग्राफ़, जिनमें कमीशन की रिपोर्टों की प्रशंसा की गई थी और दक्षिण अफ्रीका सरकार की पृथक्करण की नीति को जारी रखने पर खेद प्रकट किया था, आवश्यक दो-तिहाई बहुमत से स्वीकार कर लिये गये ।

†[THE DEPUTY MINISTER FOR EXTERNAL AFFAIRS (SHRI ANIL K. CHANDA): (a) Yes.

(b) In the Report, the Commission:

(i) continues its custom of analysing and studying the implications of new legislation and regulations in South Africa; and

(ii) presents a methodical and descriptive account of events of some significance which occurred between August 1954 and July 1955 and which affected or threw fresh light on the racial situation in South Africa.

(c) The report was considered by the *Ad Hoc* Political Committee of the U.N. General Assembly which passed a resolution on the 9th November 1955. The resolution *inter alia* requested the Commission to continue to keep under review the racial situation in South Africa and to report to the General Assembly at the next session. The resolution came up for consideration at the Plenary Session of the General Assembly on 6th December 1955. The paragraph of the resolution suggesting the reappointment of the Commission for another year failed to receive the 2/3rds majority by one vote in order to be operative. The remaining paragraphs commending the Commission's report and expressing regret at the continuation of the South African Government's policy of apartheid were adopted by the required 2/3rds majority.]

श्री कृष्णकान्त व्यास : क्या मैं जान सकता हूं कि दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों की कुल कितनी संख्या है ?

SHRI ANIL K. CHANDA: There are no Indian nationals in South Africa. There are, of course, a large number of South African citizens of Indian origin.

REQUIREMENT OF GYPSUM FOR SINDRI FACTORY

*351. MOULANA M. FARUQI: Will the Minister for PRODUCTION be pleased to state:

(a) what is the annual requirement of gypsum for the Sindri Fertilizers and Chemicals Ltd; and

(b) what percentage of this requirement is met by Messrs. Bikaner Gypsum Ltd.?

THE DEPUTY MINISTER FOR PRODUCTION (SHRI SATISH CHANDRA): (a) About 4·5 lakh tons at present.

†English translation.